

बड़े देशों की मनमानी

ऐसा बहुत कम होता है जब किसी मसले पर सुरक्षा परिषद में अमेरिका अलग-थलग दिखे। यरूशलम के मसले पर वह न केवल अलग-थलग दिखा, बल्कि शेष सदस्यों की आलोचना के निशाने पर भी आया। अपनी ऐसी स्थिति के लिए वह खुद के अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकता। एक ऐसे समय जब इस्लामी जगत अशांति एवं उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है तब अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से यरूशलम को इजरायल की राजधानी के तौर पर मान्यता देने की घोषणा करना एक तरह से जानबूझकर माहौल बिगाड़ने वाला काम है। यह सही है कि यरूशलम इजरायल की अधोषिit राजधानी जैसा है, क्योंकि संसद, सुप्रीम कोर्ट एवं विदेश मंत्रालय के साथ अन्य महत्वपूर्ण संस्थाएं वहीं स्थापित हैं, फिर भी इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि फलस्तीनी भी इस प्राचीन शहर को अपनी भावी राजधानी के रूप में देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यकायक यरूशलम को इजरायल की राजधानी के तौर पर मान्यता देने और अमेरिकी दूतावास को वहां स्थांतरित करने की घोषणा करके पहले से अशांत इस्लामी जगत को और अशांत करने का काम किया है। उन्होंने ऐसा इस आधार पर किया, क्योंकि अमेरिकी संसद ने इस आशय का एक कानून पारित कर रखा है कि यरूशलम को ही इजरायल की राजधानी होना चाहिए। बावजूद इसके एक दशक पुराने इस कानून पर अमल करने का यह सही समय नहीं। अमेरिका इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकता कि 1980 में सुरक्षा परिषद की ओर से पारित एक प्रस्ताव यह कहता है कि यरूशलम में किसी भी देश को अपना राजनयिक कार्यालय स्थापित नहीं करना। इस प्रस्ताव में यरूशलम को ऐसे पवित्र शहर के तौर पर मान्यता दी गई है जहां यहूदियों और ईसाइयों के साथ मुसलमानों का भी अधिकार है। अपनी नीतियों से दुनिया को प्रभावित करने वाले अमेरिका को इस्लामी जगत और खासकर पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात देखने चाहिए। उसे यह बुनियादी बात भी समझनी चाहिए कि अगर वही सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का अनदेखी करेगा तो फिर अन्य देशों को ऐसा करने से कैसे रोका जा सकता है? यह अच्छा हुआ कि भारत ने यह स्पष्ट किया कि वह अपनी उस पुरानी नीति पर कायम है जो सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के अनुरूप है, लेकिन और भी अच्छा यह होगा कि वह यह भी रेखांकित करे कि दुनिया के सभी बड़े देश मनमानी करने से बाज आएं। क्या यह अजीब नहीं कि चीन ने यरूशलम पर अमेरिका के फैसले का विरोध करते हुए इस पर तो चिंता की जताई कि इससे पश्चिम एशिया के हालात बिगड़ सकते हैं, लेकिन उसे यह नहीं दिखता कि पाकिस्तान के प्रति उसके रवैये के चलते दक्षिण एशिया के हालात बिगड़ने का खतरा है? वह न केवल अफगानिस्तान और भारत को अस्थिर करने वाले पाकिस्तान की पैरवी करता है, बल्कि इस क्रम में आतंकी सरगना मसूद अजहर का भी खुले आम बचाव करता है। यह ठीक है कि रूस और चीन के साथ विदेश मंत्री स्तर की बैठक में भारत ने चीन के समक्ष मसूद अजहर का मसला उठाने का निश्चय किया है, लेकिन बेहतर होगा कि वह क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों पर अपनी सक्रियता और बढ़ाए।

मुफ्त इलाज

उत्तर प्रदेश के गरीबों, किसानों और असहाय वर्ग के लोगों को मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत आच्छादित किया गया है। इसका शासनादेश शुक्रवार को जारी हो चुका है। इसके लागू होने पर अब इन लोगों को ढाई लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। कुत्रिम अंग की जरूरत पड़ने पर एक लाख रुपये तक का इंप्लांट भी मुफ्त होगा। इस सुविधा को व्यवहार में लाने और उसकी मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी संस्थागत वित्त, बीमा एवं बाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय निभाएगा। चिकित्सा शिक्षा के सभी प्रधानाचार्य, निदेशक और कुलपति इसके नोडल अधिकारी होंगे। इस बीमा से जुड़े अस्पताल सीजीएचएस की दरें पर 10 दिनों में क्लेम पेश करेंगे, जबकि बीमा कंपनी से 45 दिन के भीतर क्लेम राशि उन्हें देगी। इसके लिए किसान को नाम रेवन्यू विभाग के रिकार्ड या खतौनी में खातेदार या सहखातेदार के तौर पर लिखा होना जरूरी है। प्रदेश सरकार की अन्य कई योजनाओं की तरह यह भी एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके पूरी तरह से लागू हो जाने के बाद गरीब जनता को इलाज के लिए अपनी जमीन, घर और जेवरात बेचने नहीं पड़ेंगे और न महाजन की शरण में जा कर अनापशनाप ब्याज पर कर्ज लेना पड़ेगा। आज के दौर में अस्पतालों में इलाज अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, सरकारी अस्पतालों में भी महंगी दवा बाहर से ही खरीद कर देनी होती है। योगी सरकार से उम्मीद की जाती है कि अब तक की व्यावहारिक कठिनाइयों से सबक लेते हुए प्रदेश की जनता को यह लाभ दिलाएगी।

कह के रहेंगे	माधव जोशी
	
कल का परिणाम	
व्‍या मणिशंकर अय्‍यर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ व्‍यान से गुजरात में कांग्रेस को नुकसान होगा?	
आज का सवाल	
क्या मैक्स अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई से निजी अस्पतालों के रवैये में सुधार होगा?	81.25 हाँ 18.75 नहीं
अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें Y – हां, N – नहीं, C – कह नहीं सकते	
परिणाम एसएमएस से प्राप्त नतीजों के साथ जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।	

राहुल गांधी की राजनीतिक राह



संजय गुप्त
कांग्रेस को राजनीतिक बहुत तब मिलेगी जब बतौर अध्यक्ष राहुल गांधी स्पष्ट सोच और ठोस एवं वैकल्पिक नीतियों से लैस होंगे

आखिरकार राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनेने जा रहे हैं। अध्यक्ष पद के चुनाव की कोरी औपचारिकता में केवल उन्होंने ही नामांकन किया और अब 11 दिसंबर को उनके निर्वाचन की घोषणा पर हौनी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने उपाध्यक्ष की प्रॉन्नति से उत्साहित हो सकते हैं, लेकिन इसके आसार कम ही हैं कि वह कांग्रेस की दशा-दिशा में कोई बड़ा परिवर्तन ला सकेंगे। सच तो यह है कि पिछले दो-तीन साल से सोनिया गांधी की अस्वस्थता के चलते राहुल ही एक तरह से पार्टी की कमान संभाल रहे थे और यह किसी से छिपा नहीं कि इस दौरान पार्टी की राजनीतिक गिरावटी का सिलसिला तेज हुआ। तथ्य यह भी है कि राहुल गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष बनना राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा दिए जाने का एक और उदाहरण है। कांग्रेस नेता शहजाद पूनावाला ने राहुल के निर्वाचन की प्रक्रिया पर खुलकर सवाल उठाए, लेकिन परिवारवाद और चाटुकारिता में घिरे कांग्रेस ने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। कांग्रेस के नेता भले ही राहुल को इस प्रॉन्नति का विरोध न करें, लेकिन उनमें

से अनेक अंदर ही अंदर इस पर चिंतित हो सकते हैं कि वह अध्यक्ष के रूप में क्या कर सकेंगे? चूंकि कांग्रेस का इतिहास आजादी के आंदोलन से जुड़ा रहा और उसने लंबे समय तक केंद्र और राज्यों की सत्ता पर राज भी किया इसलिए उसकी एक राजनीतिक अहमियत है, लेकिन यह भी साफ है कि सत्ता में लंबे समय तक रहने के बाद भी वह जनता की तमाम उम्मीदों को पूरी नहीं कर सकी। नि:संदेह पहले प्रधानमंत्री के रूप में जवाहर लाल नेहरू ने देश को कई ऐसी संस्थाएं दीं जो एक स्वतंत्र-संप्रभु और लोकतांत्रिक देश के लिए आवश्यक थीं, लेकिन उन्होंने ही इंदिरा को राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया। इसका समर्थन चाटुकारिता संस्कृति वाले कांग्रेसियों ने भी किया। इसी के साथ कांग्रेस में परिवारवाद की नींव पड़ी। नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री अवश्य बने, लेकिन उनके निधन के बाद जब प्रधानमंत्री के चयन की बारी आई तो इंदिरा की मोगरजी देसाई समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं पर तरजीह दी गई। बाद में इंदिरा गांधी ने धीरे-धीरे कामराज समेत उन नेताओं को किनारे करना शुरू कर दिया जो पार्टी में बिखराव के समय उनके साथ खड़े हुए थे।

इंदिरा गांधी एक शक्तिशाली नेता के तौर पर अवश्य उभरीं, लेकिन उनके नेतृत्व में देश के आर्थिक ढांचे को मजबूती नहीं मिल सकी, क्योंकि उनकी नीतियां समाजवाद से ग्रस्त थीं। उन्होंने लाइसेंस-इम्पेक्टर राज को ही बढ़ावा दिया, जिसके चलते आर्थिक विकास की दर को उपहास स्वरूप हिंदू विकास दर कहा जाने लगा था। उन्होंने देश को काले का एक और उदाहरण है। कांग्रेस नेता शहजाद पूनावाला ने राहुल के निर्वाचन की प्रक्रिया पर खुलकर सवाल उठाए, लेकिन परिवारवाद और चाटुकारिता में घिरे कांग्रेस ने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। कांग्रेस के नेता भले ही राहुल को इस प्रॉन्नति का विरोध न करें, लेकिन उनमें



अवधेश राजगुप्त

थी। 1980 में इंदिरा को सत्ता में वापसी करने का मौका मिला तो वह पहले संजय गांधी को आगे बढ़ाने में जुटीं और फिर उनके निधन के बाद बड़े बेटे राजीव गांधी को। 1984 में उनकी हत्या के बाद राजीव गांधी जिस तरह प्रधानमंत्री बने वह भी परिवारवाद का प्रमाण ही बना। राजीव गांधी को न तो राजनीति का अनुभव था और न ही प्रशासन का। वह न तो जमीन से जुड़े थे और न ही राजनीति में आने के इच्छुक थे। बावजूद इसके कांग्रेस के चाटुकार उन्हें एक महान नेता बताते लगे। अनुभवहीनता के चलते वह खुद को मिले प्रचंड बहुमत के साथ न्याय नहीं कर सके। उन्होंने सुधार के छिटपुट प्रयास अवश्य किए, लेकिन जल्द ही गंभीर आरोपों से ऐसा धिरे कि सत्ता से बाहर हो गए। इसके बाद अल्पकालिक सरकारों ने देश को दीवालिया होने को मगार तक पहुंचा दिया। ऐसे कठिन हालात में 1991 में नरसिंह राव के नेतृत्व में बनी सरकार को और से किए गए बुनियादी आर्थिक बदलाव न केवल निर्णायक, बल्कि देश की दिशा बदलने वाले साबित हुए।

नरसिंह राव का कार्यकाल एक तरह से कांग्रेसी सत्ता का स्वर्णिम काल था। इसकी

अनदेखी नहीं की जा सकती कि यह स्वर्णिम काल तब आया जब कांग्रेस गांधी परिवार के प्रभाव से मुक्त थी। अल्पमत की सरकार चलाने के बाद भी नरसिंह राव ने नौकरशाह रहे मनमोहन सिंह को वित्तमंत्री के तौर पर साथ लेकर देश के भविष्य की नई इबारत लिखी। नरसिंह राव के नेतृत्व में लड़े गए आम चुनाव में कांग्रेस को हार मिली तो कांग्रेस में चाटुकारिता संस्कृति वाले नेता उनके खिलाफ सक्रिय हो गए और वह सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाने की पैरवी करने लगे, जबकि वह राजनीति में आने की इच्छुक नहीं थीं। कुछ समय बाद वह अध्यक्ष पद पर आसीन भी हो गईं। विडंबना यह रही कि जिन नरसिंह राव ने देश का भविष्य संभाल उनके निधन पर कांग्रेस ने उन्हें शोथित समागन देने से भी इन्कार किया। कांग्रेस के बाहरी समर्थन से चलने वाली देवेगौड़ा और गुजराल सरकार के असफल रहने पर भाजपा सत्ता में आई और उसने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में देश को एक नई दिशा एक तरह से उन्हीं नीतियों पर चलकर दी जिनका सूत्रपात नरसिंह राव ने किया था। 2004 में भाजपा की चौंकाने वाली हार के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में जब संजय की सरकार

डिजिटल युग के मानव

हास्य-व्यंग्य शहरों को स्मार्ट बनाने की जड़ोजहद में जुटी सरकार अपने इस अभियान में पता नहीं कि कितनी सफल हो पा रही है, लेकिन स्मार्टफोन ने ईसान को जरूर स्मार्ट बना दिया है। जबसे स्मार्टफोन ने हमारे जीवन में दस्तक दी है तबसे हम स्मार्ट मनुष्यत्व को प्राप्त हो चुके हैं। अब हमारे पास वक्त नहीं है रिश्तेदारी या नानेदारी निभाने का और न ही किसी से मिलने-जुलने का। सबको मिलने वाले समय में स्मार्टफोन ने जबर्दस्त सेंस लगाई है। अब फेसबुक और वाट्सएप्प पर ही हमने अपनी चौपाल जमा ली है। सास-बहू के झगड़े की खबर लेने को अब कान नहीं लगाने पड़ते, बल्कि सास-बहू हों या ननद-भाभी, सभी अपने युद्ध यहीं निपटा रही हैं। और खबर खुद व खुद चलकर हमारे पास आ रही हैं। लड़ाइयां भी अब बाल नाले या गुलमगुल्य़ा की नहीं रहीं। वर्रुअल युद्ध के बाकायदा बिगुल बजते हैं। बहसें होती हैं। आरोप-प्रत्यारोप के दौर चलते हैं। यहाँ तक कि गाली गलौज भी होती है। फेसबुक पर दुनिया पढ़ती है और वाट्सएप्प पर ऑडियो-वीडियो देख सुनकर फॉरवर्ड का दौर चलता है। यहाँ तक कि एक्चुअल लड़ाई में सिर फूटव्वल हो जाए तो लोग पहले डॉक्टर के पास नहीं जाते, बल्कि खून टपकते हुए दर्द से कराहते हुए ईसान का पहले फोटो सेशन होता है फिर मनमाफिक कहानी के साथ वाट्सएप्प -फेसबुक- ट्विटर पर अपलोड होता है तब कहीं जाकर उस ईसान का इलाज शुरू होता है। ऐसे फोटो अलग अलग ग्रुपों से होकर पर्सनल आइडी तक फॉरवर्ड होते हैं और कुछ ही देर में हजारों व्यूज तो मिल ही जाते हैं।

डिजिटल दुनिया का कमाल तो तब देखने को मिलता है जब झगड़े का निपटारा होकर शांति भी हो जाती है पर वीडियो-ऑडियो फॉरवर्ड का दौर नहीं थमता। यह कुछ इस तरह होता है कि जैसे किसी का बच्चा गुम हो गया हो और उसने वाट्सएप्प पर फोटो संग सूचना दे



अरुणा चवुर्वेदी

आज लोग सामने हाय-हेलो मले न करें, वाट्सएप्प पर रोज सुबह फूल-पत्ती और मगवान की फोटो जरूर भेजते हैं

दी, - 'बच्चा मिलते ही इस पते पर पहुँचाएँ या फलों नंबर पर फोन करें।' इस पर बच्चा मिलने के बाद भी सूचना फॉरवर्ड होती रही और आलम यह हुआ कि बच्चा बेचारा जहाँ भी जाता वहाँ से पकड़ कर घर पहुँचा दिया जाता। वाट्सएप्प या फेसबुक पर भेजी हुई सूचना या वीडियो बंदूक की गोली की तरह है जो सिर्फ छोड़ी जा सकती हैं वापस नहीं आ सकती। लोग फेसबुक और वाट्सएप्प पर यॉद प्यार का इजहार करते हैं तो वाक् युद्ध भी यहीं निपटाए जाते हैं। वो अब गए जमाने की बात हो गई जब फेसबुक पर लोग खाना-पीना, घूमना-फिरना शेयर करते थे। अब तो बाकायदा चौपाल की तर्ज पर पर के अंदर फोटो अलग अलग ग्रुपों से होकर पर्सनल आइडी तक फॉरवर्ड होते हैं और कुछ ही देर में हजारों व्यूज तो मिल ही जाते हैं।

सिर्फ पारिवारिक या सामाजिक बहसें ही नहीं, यह डिजिटल चौपाल भी असली मूल चौपाल की तरह राजनीतिक बहसों का भी अड्डा है। यहाँ अलग-अलग पार्टी के भक्त अपनी-अपनी पार्टी का भजन ही नहीं गाते, बल्कि विपक्षी पार्टी को नीचा दिखाने का हर्सप्रभ प्रयास

तथ्य-कथ्य	एक फीसद धनी लोगों के पास कुल संपति				
2016	2017				
(आंकड़े लाख अरब रुपये में)					
1.99	3.21	4.87	5.23	15.09	18.70
भारत	लैटिन अमेरिका	चीन	एशिया प्रशांत*	यूरोप	उत्तरी अमेरिका
			*भारत और चीन को छोड़कर	47.29	51.37
			34.49	35.51	59.59
					65.16

स्रोत : क्रेडिट सुइस ग्लोबल वेल्थ

तानाशाह पर लट्ठ

भारतीय मीडिया का उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग-उन के प्रति प्रेम सिर्फ दक्षिण कोरिया सरकार के लिए ही नहीं बल्कि कुछ दूसरे देशों के लिए भी कौतुहल का विषय बन गया है। दक्षिण कोरिया के नई दिल्ली स्थित राजदूतावास के अधिकारी

मीडियाकार्मियों से पूछते फिर रहे हैं कि ऐसी क्या वजह है कि एक तानाशाह को भारतीय मीडिया में इतनी जगह दी जा रही है। अब नई दिल्ली स्थित कुछ दूसरे पश्चिमी देशों के राजदूतावास में भी यह चर्चा का विषय बन गया है। यह अध्ययन किया जा रहा है कि भारत की टीवी मीडिया की तरफ से उत्तर कोरियाई तानाशाह को हर गतिविधि दिखाने के पीछे वजह क्या हो सकती है। पश्चिमी देशों के दूतावास के मीडिया से जुड़े अधिकारी यह जानने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह की भारी मीडिया कवरेज के लिए उन्हें क्या करना चाहिए।

बाबुओं का नया नुस्खा

समस्या कोई भी हो, बाबुओं के पास उसे हल करने के पचास नुस्खे होते हैं। मर्ज का इलाज करने की जगह उनका जोर ऐसे ही नुस्खे आजमाने पर होता है। कुछ ऐसा ही जीएसटी के साथ हो रहा है। जीएसटी के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों के बीच कुछ टैक्स अधिकारियों को ऐसा ही उपाय सूझा है।

राजरंग

एक आला टैक्स अफसर ने जीएसटी पर एक गाना तैयार किया है। दिल्ली के लुटियंस जोन में बैठने वाले उनके वरिष्ठ अधिकारियों को लगता है कि यह गाना सुनाकर व्यापारियों की तकलीफ दूर हो जाएगी। नॉर्थ ब्लॉक के अधिकारियों के मन में इस गाने की धुन छा चुकी है। यही वजह है कि अब वे इसे हर शहर, हर बाजार में व्यापारियों को सुनाने की बात कह रहे हैं। बहरहाल यह गाना सुनाकर व्यापारियों की तकलीफ कम हो या न हो, लेकिन बाबूओं का मन जरूर बहल जाएगा।

निकली सारी हेकड़ी

हर किसी से ठेंग पर रखने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पंडित जी इन दिनों बदले-बदले से नजर आ रहे हैं। वह ऐसे हर किसी से मिलना चाह रहे हैं, जिन्हें कल तक वह भाव नहीं देते थे। इनमें कर्मचारी, छात्र सभी हैं। इनमें से कुछ लोगों को वह विश्वविद्यालय तक से बाहर कर चुके हैं। हालांकि इस बदलाव की वजह पंडित जी के खिलाफ हर तरफ से उठ रही आवाज है। यहाँ तक कि मंत्रालय भी उनकी कार्यप्रणाली से भारी नाखुश है। जांच में उनके खिलाफ ढेरों अनियमितताओं की पुष्टि अलग से हो चुकी है। ऐसे में जब उन पर कार्रवाई का फैंदा कस चुका है, तो अब उन्हें अपनी सारी गलतियां भी समझ में आने लगी हैं। वह दिल्ली तक एग्रांच लगाने में जुटे हैं। हाल ही में उन्होंने मंत्री से लेकर विश्वविद्यालय के मुखिया तक से मिलने की जुगत में जुटे हैं। माना जा रहा है कि अब वह कुछ भी कर लें,

लेकिन उन पर फंदा इतना ज्यादा कस चुका है कि अब उन्हें इस बदलाव का कोई फायदा मिलने वाला नहीं है।

बड़ी मुश्किल होगी

साहब भला कैसे छोड़ पाएंगे सरकारी मकान, बड़ी मुश्किल होगी। सरकारी आवास को लेकर ज्यादातर साहब लोगों का प्रेम ज्यादा ही रहता है। तभी तो पद से हटने के बाद भी मकान न छोड़ना आदत में शुमार हो गया था, लेकिन चीन महीने के भीतर सरकारी आवास छोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। माननीयों के लिए भी यह एक बड़ी मुश्किल है। कई पंच वर्षीय योजनाओं तक संसद में हनक बनाने वाले माननीयों के लिए भी यही समय पुकरर किया गया है। जबकि उनके आवास का पता उनकी पहचान से बन गई है। ऐसे में आवास को छोड़ पना आसान नहीं होगा, लेकिन ऐसा ही होगा, क्योंकि कानून में संशोधन कर दिया गया है। हाल में ही कुछ माननीयों को संसद से मुक्त कर दिया गया है। राजनीतिक गलियारे में इसे लेकर चर्चा है कि जिस सरकारी मकान को बनाए रखने के लिए उन्होंने इतनी कड़ी मशकत की, अब वह ही छूटा जाए। मात्र 90 दिन में यह करना जरूरी होगा। ऐसे में यह काम उन्हें दिल पर पत्थर रखकर ही करना होगा।

बनी तो सोनिया ने प्रणब मुखर्जी के बजाय मनमोहन सिंह को इसीलिए प्रधामंत्री बनाया ताकि सब कुछ उनके हिसाब से हो सके। राव के नेतृत्व में मनमोहन सिंह ने वित्तमंत्री के रूप में जितनी सफलता हासिल की थी वह सब सोनिया के नेतृत्व में नाकामी में बदल गई। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने सोनिया के रबर स्टैप बनाा पसंद किया। हालांकि राजीव गांधी की तरह राहुल भी अनमने से होकर राजनीति में सक्रिय हुए थे, लेकिन कांग्रेस नेताओं का एक गुट जल्द ही उन्हें करिश्माई बनेने के काम में लग गया। नतीजा यह हुआ कि वह पहले महासचिव बनाए गए और फिर उपाध्यक्ष।

बोते तीन-चार सालों की राहुल की नीतियां यह बताती हैं कि उनकी कोई स्पष्ट सोच नन है। उन्होंने कभी लालू यादव के विरोध में उन्हें बचाने वाले अध्यादेश को प्रति फाड़ी और कभी उनके साथ खड़े होना बंद किया। वह उत्तर प्रदेश में सपा को सत्ता से बाहर करने निकले थे, लेकिन जल्द ही उसी से हथ मिलाकर चुनाव लड़ते दिखे। इन दिनों वह खुद को हिंदुओं के पैरोकार दिखने के लिए मंदिर-मंदिर घूम रहे हैं। कांग्रेस को बहुत तब मिलेगी जब राहुल गांधी स्पष्ट सोच और ठोस एवं वैकल्पिक नीतियों से लैस होंगे। वैकल्पिक विचार के नाम पर राहुल लोकलुभावन तौर-तरीकों से लैस हैं। मुक्त अर्थव्यवस्था के इस दौर में इन तौर-तरीकों के लिए कोई जगह नहीं। देश को एक मजबूत विपक्ष के लिए मंदिर-मंदिर घूम रहे हैं। लोकतांत्रिक तौर-तरीकों को मजबूती मिलेगी। यह अजीब है कि जब राहुल को लोकतांत्रिक तौर-तरीकों को बल देना चाहिए तब वह दिखावटी तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष बन रहे हैं। ऐसे में यही लगता है कि यदि कभी कांग्रेस राहुल के नेतृत्व में सफल होगी तो उसका कारण भाजपा की गलतियां ही अधिक होंगी।

response@jagran.com



ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है, कल्पना करने की ताकत दी है और कल्पना ही यथार्थ बनती है। सब कुछ संभव है यदि हमारा नजरिया सकारात्मक बन जाय। सकारात्मक कल्पना जीवन को सुरंरतम बना देती है। वहीं जो व्यक्ति सुरंदरतम कल्पना को मन में बसाने की कोशिश नहीं कर सकता, वह अच्छा जीवन भी नहीं जी सकता। विश्वप्रसिद्ध मोटीवेशनल लेखक नॉर्मन विन्सेंट कहते हैं कि, ‘कल्पना सच्चा जादुई ग्लोबल का है। मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि ईसान अपना मानसिक नजरिया बदलकर अपनी जिंजीगी बदल सकता है। अवसर जीवन में ऐसे लोगे देखे जाते हैं, जो कई बार इस बात का बहाना लेते हैं कि परिस्थितियां उनके प्रतिकूल थीं, इसलिए वे जीवन में बेहतर नहीं कर पाए अथवा जिस लक्ष्य तक जाना चाहते थे वहाँ तक नहीं पहुँच सके। दरअसल यह सच नहीं है बल्कि इसके पीछे का सच यह है कि उन्होंने इस नजरिये से सोचा ही नहीं था कि वे जीत सकते हैं। अमेरिका के उद्योगपति हेनरी फोर्ड ने जीवन में अनेक बाधाओं का सामना कर अपने नजरिये को मजबूत बनाकर पूरे विश्व के सामने एक पहचान बनाई। उनका भी मानना है कि, ‘अगर आप सोचते हैं कि आप किसी काम को कर सकते हैं या अगर आप सोचते हैं कि आप किसी काम को नहीं कर सकते हैं, तो दोनों ही स्थितियों में आप सही हैं।' ऐसा इसलिए है, क्योंकि दोनों ही स्थितियां व्यक्ति के नजरिये से उसके मस्तिष्क में फिट हो जाती हैं।

जब व्यक्ति हार मानना आरंभ कर देता है तो शारीर की शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया ऐसे रसायनों का स्राव करती है, जो व्यक्ति को निष्क्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं व्यक्ति हर स्थिति में जब यह नजरिया बना लेता है कि उसे जीतना है और हर हाल में लक्ष्य तक पहुँचना है तो वही बाधा उसके लिए पुनः का काम करती है और मंजिल तक पहुँचाते हैं। इतिहास भी यही कहता है कि सभसे महान विजेताओं को जीतने से पहले आमतौर पर बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ा था। वे इसलिए जीते, क्योंकि उन्होंने अपनी पराजयों से हताश होने से इन्कार कर दिया था और अपने नजरिये में इस सब को रचा बसा लिया था कि असंभव कुछ नहीं होता, सब संभव हो जाता है जब नजरिया सकारात्मक होता है।

रेनू सैनी

ट्वीट-ट्वीट	
	
मणिशंकर अय्यर की बदजुबानी के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं पर सख्ती की है। ऐसा ही संदेश भाजपा के शीर्ष नेताओं को भी अपने बयानवीरों के लिए देना चाहिए जो मर्यादा लांघने में किसी से कम नहीं।	
अजित अंजुम@ajitanjium	
दोषियों की पहचान कर उन पर कार्रवाई करने के बजाय मैक्स अस्पताल का लाइसेंस रद्द करना सुविधियां घुराने और लोकप्रियता हासिल करने के लिए उठाया गया कदम है। इससे तमाम मरीजों और निरदोष कर्मचारियों के हितों को भी भारी नुकसान होगा।	
शेखर गुप्ता@ShekharGupta	
	
यहाँ तक कि एकदलीय तानाशाही वाले चीन में भी स्थानीय निकाय बेहद ताकतवर हैं। उन्हें तमाम अधिकार हासिल हैं। उसी तर्ज पर हमें भी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाकर स्थानीय लोकपाल के जरिये उन्हें जवाबदेह बनाना चाहिए। जयप्रकाश नारायण@JP_LOKSATTIA	
शहजाद पूनावाला, मणिशंकर अय्यर और अब सलमान नियाजी को देखकर लगता है कि भाजपा कांग्रेस को उसके मोहरों से ही मात देने पर आमादा है। पाटी अपनी उपलब्धियों और विकास के बजाय विपक्षी कांग्रेस पर ही हमलावर है। रिस्ता प्रकाश@smiitaprakash	
जनपथ	
शायी इटली में करो या लंदन में जाय, बहुभोज में साथियों को लेना बुलाये	
को लेना बुलाये लगाएंगे सब दुमका, चोरी-चोरी ताक बहुरानी का झुमका।	
होता जश्न 'विाट' मिले जब सभी-साथी, मजा न आए यार होये जब घुप-घुप साथी।	
- ओमप्रकाश तिवारी	